



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 250]
No. 250]नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 29, 2007/भाद्र 7, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 29, 2007/BHADRA 7, 1929

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(समन्वय अनुभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2007

सं. 5/2/2004-समन्वय.—सरकार ने 20 सितम्बर, 2004 के संकल्प संख्या 5(2)/2004-आईसीसी के तहत असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया था। आयोग का कार्यकाल दिनांक 10-2-2005 के संकल्प संख्या एफ. 5(2)/2004-एसएसआई(सी) के तहत दिनांक 20-9-2004 से एक वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष किया गया था। आयोग के नाम को ‘असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग’ से बदलकर दिनांक 9-5-2005 के संकल्प संख्या 5(2)/2004-एसएसआई(सी) के तहत ‘असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग’ किया गया था।

2. सरकार ने अब आयोग का कार्यकाल 30 सितम्बर, 2008 तक बढ़ाने का निर्णय किया है।
3. 20 सितम्बर, 2004 के संकल्प की अन्य निबंधन और शर्तें यथावत बनी रहेंगी।

प्रवीर कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(COORDINATION SECTION)

RESOLUTION

New Delhi, the 23rd August, 2007

No. 5/2/2004-CDN.—The Government constituted a National Commission on Enterprises in the Unorganised/Informal Sector under Resolution No. 5(2)/2004-ICC, dated 20th September, 2004. The term of the Commission was extended from one year to three years w.e.f. 20-9-2004 vide Resolution No. F. 5(2)/2004-SSI(C) dated 10-2-2005. The name of the Commission was changed from ‘National Commission on Enterprises in the Unorganised/Informal Sector’ to ‘National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector’ vide Resolution No. 5(2)/2004-SSI(C) dated 9-5-2005;

2. The Government has now decided to extend the term of the Commission up to 30th September, 2008.
3. The other terms and conditions in the Resolution dated 20th September, 2004 will remain unchanged.

PRAVIR KUMAR, Jt. Secy.